

नहर, कुआँ, सिंचाई साधन, जल का हो विस्तार, खेत जल वितरण प्रणाली से सींचे हर खेत अपार।
बूँद-बूँद से फसल संवरे, समृद्ध हो किसान हर बार।
CBC 35101/13/0114/2526

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB – G RAM G
(विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025

125 दिन
की रोजगार गारंटी

RED-X
B.W.P. PLY,
BOARDS& DOORS
'X' Factor that Makes A Difference
Stockist :
GULAB CHAND LAL CHAND& Co.
9831114555
9874415555

कोलंबो में भारत-पाक मुकाबले पर तिलक ने कहा, हम तैयार हैं (पृष्ठ 8)

चांदी 4.000 रुपये बढ़कर 2.68 लाख रुपये पर, सोना भी मजबूत (पृष्ठ 8)

‘घर-घर जायें, नो मैपिंग श्रेणी के वोटर्स की करें जांच’

तृणमूल सुप्रिमो ममता ने पार्टी के बीएलए-2 के साथ बैठक में दिए निर्देश

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत 14 फरवरी तक सुनवाई होगी। यानी, सुनवाई खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसी बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए-2) के साथ अहम बैठक की। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रिमो ममता बनर्जी ने बीएलए-2 से कहा कि अब तक जिन मतदाताओं के नाम नो मैपिंग श्रेणी में हैं, उनके घर-घर जायें और जांच करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मतदाता सूची से



जिनका भी नाम कटा है या जिन्हें अब तक अनमैपड बताया गया है, उन सभी लोगों के घर जायें और खुद देखें कि वहां कोई है या नहीं। ममता ने बीएलए-2 से कहा कि राज्य में

जान-बूझकर वैध मतदाताओं के नाम काट जा रहे हैं, इसलिए हमें इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों के नाम तार्किक विसंगतियों (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज) की लिस्ट में हैं, उसकी पूरी जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटायें गये हैं, उन सभी वोटर्स के घर-घर जाकर जांच करें, ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके।

‘वायुशक्ति’ में भाग लेंगे राफेल, तेजस; ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में वायुसेना की सफल भूमिका की झलक पेश करेंगे

नयी दिल्ली : सैन्य अभ्यास ‘वायुशक्ति’ में राफेल, सुखोई-30, मिग-29, तेजस, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की सफल भूमिका की झलक पेश करेंगे। वायुसेना के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वायुशक्ति 27 फरवरी को राजस्थान में ‘पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज’ में आयोजित किया जाएगा। वायुसेना उपाध्यक्ष एयर मार्शल नागेश कपूर ने बताया कि राजस्थान के पोकरण में इस सैन्य



शक्ति अभ्यास के दौरान लंबी दूरी के लक्ष्य बनाने का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्विवार्षिक इस अभ्यास को काफी महत्वपूर्ण



मूल्यांकन 2026 में पूर्ववत भौतिक रूप से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कदम से समन्वय बेहतर होगा और अंकों के जोड़-घटाव में होने वाली त्रुटियां समाप्त होंगी। भारद्वाज ने कहा, डिजिटल मूल्यांकन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज होगी और अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में रहकर नियमित कार्य करते हुए मूल्यांकन कर सकेंगे।

बांग्लादेश में आम चुनाव आज

50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्र ‘संवेदनशील’

ढाका : बांग्लादेश में गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के लगभग 18 महीने बाद हो रहे हैं। जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को गिरा दिया था। उस समय अवामी लीग का नेतृत्व था। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने

कार्यभार संभाला था। देश में 13वें संसदीय चुनाव 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ हो रहे हैं। हसीना की अवामी लीग को चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) सबसे आगे चल रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे और राजधानी ढाका में ‘बॉडी कैमरे’ लगाए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है।

व्यापार समझौते में सरकार अमेरिका के सामने झुक गई : राहुल

नयी दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार झुक गई और उसे इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का समझौता करने को विवश हुए क्योंकि अमेरिका का उन पर दबाव है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सत्तापक्ष को इससे नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए अमेरिका में एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ दर्ज मामले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एक प्रकरण का उल्लेख किया, जिस पर पीठासीन सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड



में शामिल नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा, “मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में क्या हुआ। अगर हम ‘इंडिया’ गठबंधन (की सरकार में) अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे होते, तो हम एक बात बिल्कुल साफ करते कि इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज भारतीय डेटा है। अगर अमेरिका डॉलर को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसे यह मानना होगा कि भारतीय डेटा एक रणनीतिक पूंजी है और किसी भी चर्चा को बराबरी के स्तर पर होना चाहिए, मालिक और नौकर की तरफ से।”

राहुल गांधी के झूठे बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध करेंगे: रीजीजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी का भाषण “झूठ से भरा” था और सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किये गए “झूठे” दावों को सदन की कार्यवाही से हटायें जाने का अनुरोध करेंगे। केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण के तुरंत बाद, रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आसन को एक नोटिस देंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोले गए किसी भी कथन के प्रमाणीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “राहुल गांधी ने जो भी झूठ बोला है, हम उसे रिकॉर्ड से हटायें जाने की मांग करेंगे।” हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयानों को प्रमाणित करने का वादा किया है, लेकिन मंत्री ने कहा, “मुझे पता है कि वह उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने सदन में झूठ बोला है।”

कांग्रेस ने देश को बेचा, मोदी ने नहीं : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठक में भारत के हितों से समझौता करके आई थी। उन्होंने बजट पर चर्चा में राहुल के भाषण को लेकर उन पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके नरेन्द्र मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और “उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।” सीतारमण ने बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2013 में (इंडोनेशिया के) बाली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कांग्रेस समझौता करके आई थी। उन्होंने दावा किया, “इस समझौते के कारण 2017 से भारत में किसान से कोई खरीद नहीं हो सकती थी। हम राशन की दुकान से गरीबों को कुछ नहीं दे सकते थे।”



निर्वाचन आयोग बंगाल की 78 बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र करेगा स्थापित

आवासीय समितियों की सूची 25 फरवरी को होगी प्रकाशित

कोलकाता, समाज्ञा : निर्वाचन आयोग ने राज्य के 78 बड़े आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और इन आवासीय समितियों की सूची 25 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों की स्थापना के लिए 78 आवासीय परिसर चिह्नित किए गए हैं।

विस्तृत सूची 25 फरवरी को सार्वजनिक की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आने की आशंका है, इसलिए मतदान केंद्रों की कुल संख्या भी कम हो जाएगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले कई निवासी मतदान केंद्रों के दूर होने के कारण अक्सर मतदान नहीं करते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा

कि अनुभव से पता चलता है कि जब मतदान केंद्र दूर होते हैं, तो कई मतदाता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, मतदान करने नहीं आते हैं। बड़े आव-सीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने से मतदान अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि 300 से अधिक पंजीकृत मतदाताओं वाले आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

ट्रेड यूनियनों की आज हड़ताल, आवश्यक सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

नयी दिल्ली : केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल की वजह से बृहस्पतिवार को पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ-साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। 12 फरवरी को होने वाली आम हड़ताल में अलग-अलग क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने की उम्मीद है। ट्रेड यूनियनों के एक समूह ने नौ जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था ताकि “केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और देश-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों का विरोध” दिखाया जा सके। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई भाषा को बताया, “12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की वजह से बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गैस और जलपूर्ति की सेवाओं पर असर पड़ेगा।” उन्होंने बताया कि सभी बैंक यूनियन हड़ताल में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनका यूनाइटेड फ्रंट 27

हड़ताल पर बंगाल सरकार का कड़ा रुख, अनुपस्थित कर्मचारियों का कटेगा वेतन व होगी कार्रवाई

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य सचिवालय नवात्र ने 12 फरवरी को 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी हड़ताल (भारत बंद) के आह्वान का कड़ा विरोध किया है। वित्त विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालय यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यालय भी उस दिन खुले रहेंगे और सभी कर्मचारियों को काम पर आना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 12 फरवरी (गुरुवार) को किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा, चाहे वह आधे दिन का हो या पूरे दिन का। यदि उस दिन अनुपस्थिति मानी जाती है, तो उसे अस्थायी अनुपस्थिति माना जाएगा और उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, 11 फरवरी से पहले गंभीर बीमारी के कारण छुट्टी पर है, या 11 फरवरी से पहले स्वीकृत बाल देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश या अर्जित अवकाश पर है, तो उसकी अनुपस्थिति स्वीकार्य मानी जा सकती है।

जनवरी को पहले ही हड़ताल कर चुका है। हालांकि, एआईबीईए, एआईबीओए और बीईएफआई जैसी बैंक कामगार यूनियनें विलेध में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा, कौर ने कहा कि खनन और गैस पाइपलाइन क्षेत्र

पर भी इस आंदोलन का असर दिखने की उम्मीद है। बीमा क्षेत्र के कर्मचारी इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की इजाजत देने और नए श्रम कानून लागू करने के सरकार के फैसले का विरोध करेंगे।

सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया: सीतारमण

राज्यों को केंद्र से राजस्व का 41% हिस्सा मिलता है

मेडिकल हब, टेक्सटाइल पार्क, केमिकल पार्क से रोजगार सृजन होगा

नयी दिल्ली : लोकसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त वित्तीय राशि नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र के राजस्व में राज्यों का जो भी हिस्सा बनता है, वह दिया गया। केंद्र के राजस्व का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया गया। लेकिन केंद्र की तरफ से वसूले जाने वाले सेस से सरचार्ज में राज्यों को हिस्से-सेदारी नहीं दी गई। उन्होंने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र के ग्रास टेक्स रेवेन्यू में सेस और सरचार्ज दोनों शामिल होता है और जब सेस व सरचार्ज को हटा देते हैं तो वह नेट प्रोसिड कहलाता है और नियम के मुताबिक उस नेट प्रोसिड का 41 प्रतिशत राज्यों को दिया गया। सेस



शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मद में एक खास हिस्सा के लिए लिया जाता है। कोई भी राज्य केंद्र के पास इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो केंद्र सहयोग करता है। इस बार के बजट में मेडिकल हब, एजुकेशन हब, विशेष प्रकार के निर्माण क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है। अब इसके लिए कोई राज्य अपने प्रस्ताव लेकर केंद्र के पास आ सकता है। हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। ‘केमिकल पार्क... बंगाल आ सकता है आगे’

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मद में कैपेक्स के रूप में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.22 लाख करोड़ की घोषणा की

गई है, लेकिन इंफ्रा विकास के लिए राज्यों को जो लंबे समय के लिए कर्ज के रूप में दिए जाते हैं, उस राशि को जोड़ दिया जाए तो कैपेक्स के मद में 17.1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया जो जीडीपी का 4.4 प्रतिशत होता है। केमिकल पार्क की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल इसके लिए आगे आ सकता है।

एक लाख नई नौकरियां पैदा होंगी- वित्त मंत्री

बजट में रोजगार सृजन पर वित्त मंत्री ने बताया कि पांच रिजनल मेडिकल हब व एजुकेशन हब से युवाओं को रोजगार करने के साथ उद्योगों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। मेडिकल हब से युवाओं के रोजगार के लिए एक लाख अवसर निकलेंगे। पांच नए लेजर व टेक्सटाइल के पार्क बनाए जाएंगे और यहां भी बड़ी संख्या में रोजगार निकलेगा। बुजुर्गों की देखभाल के लिए अगले वित्त वर्ष में 1.5 लाख लोगों को कुशल बनाया जाएगा।

जमानत मांगते समय आरोपी के पूर्व के अपराध का खुलासा करना अनिवार्य: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमानत मांगने वाले प्रत्येक आरोपी का यह दायित्व है कि वह जमानत संबंधी निर्णयों में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए हलफनामे के माध्यम से अपने पूर्व के अपराध का खुलासा करे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमगनुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जमानत मांगने वाले आरोपी या आवेदक का यह दायित्व है कि वह न्यायिक विवेक के प्रयोग को सीधे प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का निष्पक्ष, पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना, छिपाना या चुनिंदा रूप से प्रकट करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आपराधिक न्याय प्रशासन की मूल नींव पर प्रहार करता है। इसने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि जमानत आवेदनों में प्राथमिकी संख्या और तिथि, संबंधित पुलिस थाने का नाम, जांच एजेंसी द्वारा लगाई गई धाराएं और कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा आदि का उल्लेख होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है

कि वह इस फैसले की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार नियम को भेजे। उच्च न्यायालय अपने नियम बनाने की शक्तियों के अनुरूप उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करने या अपने-अपने नियमों में उपयुक्त प्राधान्य शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए इस फैसले की एक प्रति जिला न्यायापालिका को भी भेजी जाए।” वकीलों को फर्जी डिप्टी प्रमाणपत्र जारी करने के आरोपी व्यक्ति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए ये निर्देश दिए गए।

हितधारक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की ज़रूरत है। कोर्ट ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ़ॉंड सीधे-सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठा खताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है।

इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की ज़रूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये ज़रूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले-भाले लोगों को जिस तरह साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 12 फरवरी, गुरुवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2082, फाल्गुन कृष्णपक्ष दशमी, 12:20 तक, नक्षत्र : ज्येष्ठा, 13:33 तक, योग : हषष्णा, 27:00 तक, सूर्योदय: 06:11, सूर्यास्त: 17:31, चन्द्रोदय : 02:08, चन्द्रास्त: 12:46, शक सम्वत: 1947 विश्वाख्य, सूर्य राशि : मकर, चन्द्र राशि : वृश्चिक, राहू काल : 13:15 14:39

राशिफल

मे़ष : मे़ष राशि के जातकों को जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। राशि का स्वामी मंगल-नीच राशि की संगति में है। ऐसे में आपको कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला सीखनी पड़ेगी।
वृष : आज का दिन संतोष और शान्ति का है। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से कुछ ग़हत मिलेगी।
मिथुन : आज किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय बना रहेगा। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में सफलता का समाचार मिलेगा। सायंकाल में कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा।
कर्क : कर्क राशि के जातकों के आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राज्य-मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होने का समय है। यात्रा आपके लिए सुखद व लाभदायक रहेगी।
सिंह : सिंह राशि के जातकों के लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा, प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी।
कन्या : गुरुवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य वृद्धि कराने वाला रहेगा। रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में सफलता मिलेगी। शुभ खर्चा व कीर्ति की वृद्धि होगी।
तुला : तुला राशि वालों के लिए दिन चारों ओर से सुखद रहने वाला है। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी। कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल होग।
वृश्चिक : आपकी राशि पर पंचम शनि एवं द्वितीय भाव चन्द्र योग अभी सात दिन और चलेगा। इसके फलस्वरूप कुछ आन्तरिक विकार जैसे-बायु-मूत्र-रक्त, जड़ जमा रहे हैं।
धनु : आज आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन सत्ता पक्ष से निकटता व गठजोड़ का लाभ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है।
मकर : आपको पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास सफल रहेंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी पर्याप्त मिलेगा।
कुम्भ : आज आपके स्वास्थ्य सुख में व्यवधान आ सकता है। राशि का स्वामी शनि क्योंकि मार्गी उदय चल रहा है। कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है।
मीन : आज का दिन पुत्र, पुत्री की चिंता में व्यतीत होगा। दौंपत्य जीवन में कई दिन से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा। बहनोंई और साले से आज लेन-देन न करें सम्बन्ध खराब होने का खतरा है।

योगी के बजट से 2027 की बिसात, आंकड़ों के सहारे सियासी दांव



अजय कुमार

पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है। पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बढ़े इस आकार को सत्ता पक्ष विश्वास का बजट बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है।

सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016-17 में जहां जीएसडीपी करीब

12.75 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं आठ-नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है।

प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016-17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है।

गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम

नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं।

रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24



प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां, 1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां, 60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रही। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाती है। युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती

यूपी : योगी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट

- युवाओं और किसानों के लिए खोला खजाना**
- सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान मुख्य थीम**
- लखनऊ :** योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने यूपी विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह योगी सरकार का 10वां व उसके दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है।
- हमारी सरकार ने चोतरफा विकास किया - वित्त मंत्री सुरेश खन्ना**

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तर्फ विकास हुआ है, चाहे वह कानून-व्यवस्था को मजबूत करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ाना हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, रोज-गार पैदा करना हो, महिला

सशक्तिकरण हो, युवाओं का प्रतिक डेवलपमेंट हो, किसानों की

खुशहाली हो और गरीबी खत्म करना हो।’

बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 फीसदी ज्यादा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इसमें शिक्षा को 12.4 प्रतिशत और चिकित्सा को छह प्रतिशत बजट आवंटित किया है। राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत रखते हुए सरकार ने युवाओं के लि् ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ और किसानों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। इस बजट के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रति व्यक्ति आय बढ़े 1,09,844 रुपये, बेरोजगारी दर घटकर 2.24 फीसदी

प्रदेश का यह बजट 9 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,09,844 रुपये हो गई है, जो 2016-17 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक इसे 1,20,000 रुपये तक



पहुंचाया जाए। प्रदेश की जी.एस.डी.पी में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.24 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है।

युवाओं के लिए रोजगार और एआई मिशन

युवाओं के लिए सरकार ने ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना और एआई मिशन की शुरुआत की है। पुलिस विभाग में अब तक 2,19,000 से अधिक भर्तियां काी जा चुकी हैं और 83,122 पदों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण देकर हर वर्ष एक लाख

सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं।

किसानों को मुफ्त बिजली और सौर ताेंतें

किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति जारी रखी है। गन्ना किसानों को रिकार्ड 3,04,321 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 3.12 करोड़ किसानों

धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने पर योगी सरकार का विशेष जोर

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खाह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जैन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खन्ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुननिर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सदन को यह भी बताया कि श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग (रामपथ) का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है।

के खातों में 94,668 करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और ‘सेफ सिटी’

महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए ‘सेफ सिटी’ परियोजना के तहत सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्काड को मजबूत किया गया है। वर्किंग वूमैन हॉस्टल का निर्माण और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। ‘महिला सामर्थ्य योजना’ के तहत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र

में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की जा रही हैं। महिला गन्ना किसानों को पर्वी निर्गमन में भी प्राथमिकता दी जा रही है।

तकनीक और भविष्य की योजनाएं

सरकार ने प्रदेश में ‘स्टेट डाटा अथॉरिटी’ और ‘डाटा सेंटर क्लस्टरस’ की स्थापना का निर्णय लिया है। उभरती हुई तकनीकों के लिए ‘नयी और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन’ बनाया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ योजना लाई जा रही है।

राजस्थान बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स

जयपुर : राजस्थान सरकार ने बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परीक्षण के लिए उच्च

स्तरीय समिति गठित करने का ऐलान किया है। यह समिति कर्मचारी संगठनों की मांगों का तुलनात्मक अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देगी। साथ ही पदोन्नति के समुचित अवसर और वेतनमान संशोधन को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रावधान किया जाएगा। यदि चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष के भीतर सेवा परित्याग, मृत्यु या

अन्य कारण से पद छोड़ता है तो वर्गवार प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

महिला कर्मचारियों को विशेष राहत
महिला कर्मचारियों को वर्तमान में तीन चरणों में तीन वर्ष तक चाइल्ड केयर लीव मिलती है। एकल महिला कर्मचारियों के लिए इसे दो चरणों में स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। सरोगेसी के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है।

पेंशनर्स के लिए आसान प्रक्रिया
पारिवारिक पेंशन पाने वाले



दिव्यांग बच्चों को अब हर वर्ष स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी; एक बार प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। पेंशनर्स मोबाइल ऐप के जरिए पेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

अनुकम्पा नियुक्ति का

वर्ग पहेली नं. 3349

1	2	3	4	5	6
		7	8		9
10		11	12	13	
		14		15	16
17	18		19	20	
			21	22	
23		24			25
			26	27	28
29				30	

बायें से दायें:-
2) इच्छा, 4) कीचड़, 7) हिजड़ा, 9) तल्लीन, 10) चौकीदार, 12) जल्दी-जल्दी, 14) थोखे की बात; रीति-रिवाज, 15) आगामी दिन, 17) चुनौती, 20) अनैतिक, 21) परंपरावि्ध, 23) चमक्रीला, 25) जान, 26) समयसारणी, 29) घनुर्धारी, 30) पुत्री.
ऊपर से नीचे:-
1) बेरहम; निर्दय, 2) उल्लू; इंद्र; पारसी धर्मा-

सुडोकू-पहेली-3307					
	9		6		
3					
2	1	5			7 8
	3			1 2	
		2		9	
			4 7		3
8 7		1		4 9	
	4				
		3			5

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।												
सूडोकू पहेली - 3306 का उत्तर												
6	1	4	5	7	9	3	2	8				
2	9	3	8	6	4	5	1	7				
5	7	8	2	1	3	6	9	4				
8	6	1	4	3	7	2	5	9				
4	3	5	9	8	2	7	6	1				
7	2	9	6	5	1	8	4	3				
1	8	2	7	9	5	4	3	6				
3	5	7	1	4	6	9	8	2				
9	4	6	3	2	8	1	7	5				

भूपेंद्र यादव ने राज्य में ‘खराब शासन और भ्रष्टाचार’ को लेकर टीएमसी सरकार की कड़ी आलोचना

कोलकाता, समाज्ञा : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार की कथित खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर आलोचना की और विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए उसके ‘वोट-ऑन-अकाउंट विधेयक’ को ‘विदाई दस्तावेज’ करार दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर मनरेगा योजना में अनियमितताओं, पीएम आवास योजना के धनकोष के उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करने और पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इस दिन, नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्रु अधिकारी की उपस्थिति में साल्टलेक के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा अनिवार्य दिशा बैठकें आयोजित नहीं की गईं और पीएम-किसान जैसी योजनाएं राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं की गईं। दिशा का उद्देश्य जिलों के कुशल, समावेशी और समयबद्ध विकास के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। पिछले



सप्ताह राज्य विधानसभा में पेश किए गए लेखा-पत्र में आबंटन का हवाला देते हुए, यादव ने दावा किया कि विज्ञान की शिक्षा के लिए धनराशि कम है, जबकि मदरसों को केवल 5,713.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग तीन करोड़ की आबादी वाले उत्तर बंगाल को केवल 910 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य कम पूंजीगत व्यय के साथ अपना काम कर रहा है और आय में वृद्धि किए बिना लगातार कर्ज ले रहा है। यह न केवल टीएमसी का आखिरी बजट

है, बल्कि उसका विदाई दस्तावेज भी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वृद्ध और उद्योगों में अपार संभावनाएं होने के बावजूद, राज्य सरकार एक स्पष्ट विकास योजना प्रस्तुत करने में विफल रही है। यादव ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं को ठीक से लागू करने में विफल रही है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि हाल ही में, पेश किए गए केंद्रीय बजट में समावेशी विकास का खाका प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत

मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में यूएपीए पर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करे एनआईए : शीर्ष अदालत

राज्य सरकार की एनआईए जांच के खिलाफ अपील पर सुनवाई

नयी दिल्ली/कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को निर्देश दिया कि वह मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा और अशांति से संबंधित एक मामले में आतंकवाद से जुड़े कठोर प्रावधानों वाले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के इस्तेमाल का औचित्य स्पष्ट करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करे। राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए प्रधान न्यायाधीश सुनकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए की जांच के खिलाफ अपनी शिकायतों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाने के लिए भी कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता



उच्च न्यायालय इस मामले में एनआईए जांच का आदेश देने के केंद्र के फैसले को राज्य सरकार द्वारा दी गई चुनौती की भी पड़ताल कर सकता है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने एनआईए से पूछा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा की जांच को उचित ठहराने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के प्रावधानों को लागू करने का आधार क्या था। बता

दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। एनआईए ने मामले में यूएपीए की धारा 15 (1) (ए) लागू की। पीठ ने एनआईए को इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने यह भी कहा कि एनआईए ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में यूएपीए के प्रावधान लागू होते हैं, जबकि राज्य पुलिस ने एनआईए को केस डायरी या संबंधित दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि दस्तावेजों को देखे बिना ही आपने कहा है कि यूएपीए की धारा 15 उचित है। केस डायरी आपके सामने पेश नहीं की गई, यह एक पूर्व-निर्णय है। हर भावनात्मक आवेश को आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।

पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर के बेटे के साथ साइबर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञा : भुवनेश्वर में एक कॉलेज के विद्यार्थी को निदेशक (सुरक्षा) और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के बेटे से 'ऑनलाइन पेइंग गेस्ट (पीजी)' आवास उपलब्ध कराने की आड़ में धोखाधड़ी करके 30,000 रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि इस विद्यार्थी से और पूछताछ करने के लिए उसे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से कोलकाता लाया गया। अधिकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता पीयूष वर्मा दिल्ली में पीजी आवास की ऑनलाइन खोज कर रहे थे तभी उन्हें एक ऐसी वेबसाइट मिली जिसमें फिरफे के कई विकल्प उपलब्ध थे। अधिकारी ने कहा कि एक संपर्क/मकान चुनने के बाद, वर्मा ने वेबसाइट के अधिकारियों से संपर्क किया जिसके बाद कथित तौर पर बुकिंग की पुष्टि के लिए उनसे 30,000 रुपये अग्रिम ऑनलाइन भुगतान करने को कहा गया। उन्होंने वेबसाइट पर दिए गए बैंक खाते में राशि डाल दी। अधिकारी का कहना है कि काफी समय तक इंजाच करने के बावजूद वर्मा को बुकिंग की कोई पुष्टि नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने वेबसाइट



पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन ये प्रयास भी विफल रहे। उन्होंने बताया कि तब वर्मा को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ और उन्होंने कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार स्थित साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने कहा कि लेनदेन से जुड़े बैंक खाते के विवरण का विश्लेषण करते पर हमने पाया कि आरोपी भुवनेश्वर में है और फिर उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसकी भूमिका का पता लगाया जा सके और यह भी पता लगाया जा सके कि क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित धोखाधड़ी का दायरा कितना व्यापक है।

हाई कोर्ट ने पाँक्सो मामले में गवाहों से दोबारा जिरह करने की दी अनुमति

7 गवाहों से फिर होगी पूछताछ

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में पीडितों या गवाहों को दोबारा न बुलाने के स्थापित नियम का अपवाद पेश करते हुए पाँक्सो मामले में गवाहों से दोबारा जिरह करने की अनुमति दी है और कहा है कि प्रत्येक मामले में निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अंबिका सिन्हा राय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सात प्रमुख गवाहों से दोबारा जिरह करने की याचिका अस्वीकार कर दी गयी थी, हालांकि

उन्होंने न्यायाधीश की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि नौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाँक्सो) मामलों में जोखिम की आंशका वाले गवाहों को आरोपी के अनुरोध पर तुच्छ आधार पर बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए। उत्तर और मध्य अंडमान की निचली अदालत के न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि पाँक्सो मामलों में पीडित/गवाहों को दोबारा बुलाने से तब तक बचा जाना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ब्लेयर सफ्टिन्ग ट्टर द्वारा पांच फरवरी को दिए गए फैसले में, न्यायमूर्ति राय

ने कहा कि विशेष पाँक्सो अदालत के न्यायाधीश की टिप्पणी 'बिल्कुल सही थी और इस मामले में कोई दो राय नहीं हो सक', लेकिन प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

विशेष पाँक्सो अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता को 2022 में एक लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय की पीठ ब्लेयर सफ्टिन्ग ट्टर की एक खंडपीठ ने 2024 में उसकी दोषसिद्धि और 10 साल के कठोर कारावास की सजा को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता से दोबारा जिरह का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के

डीए भुगतान पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे : शुभेंद्रु अधिकारी

महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर जारी विवाद पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्रु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। शुभेंद्रु अधिकारी ने साफ कहा कि डीए से जुड़ा मामला अब किसी भी तरह से न्यायाधीन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसे पहले ही 'क्लोज्ड बैचर' घोषित कर चुका है। इस दिन, साल्टलेक में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शुभेंद्रु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हालिया संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया था कि डीए का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। इस पर, प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंद्रु ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि यह मामला अब न्यायाधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मामला पूरी तरह निपटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, यह भी तय कर दिया गया है कि बकाया डीए का भुगतान किस तरह एरियर के माध्यम से किया जाएगा। शुभेंद्रु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार-बार न्यायिक व्यवस्था का अपमान कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मार्च महीने के भीतर बकाया डीए की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कानूनी विकल्प अपनाने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना ही होगा।

की जीडीपी बढ़कर लगभग 4.18-4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो जापान से अधिक है,

और देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कुलतली अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तारी में देरी पर हाई कोर्ट ने जताई गहरी नाराजगी

कोलकाता, समाज्ञा : दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज एक अपहरण मामले की जांच में धीमी प्रगति और आर-पी की गिरफ्तारी न होने पर कोलकाता हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायाधीश देवांशु बसक की डिविजन बेंच ने कहा कि इतने समय बाद भी आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने से मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है। न्यायाधीश बसक ने सवाल उठाया, भले ही यह दीवानी विवाद हो, क्या इसे अपहरण जैसी गंभीर फौजदारी शिकायत में गिरफ्तारी से रोकना जा सकता है? 2023 से जांच में कोई गति नहीं दिखाई दी। आरोपी जमानत पर नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और पूछताछ क्यों नहीं की गई? राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि अपहृत व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसके तथा आरोपी के बीच दीवानी विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपहृत का मोबाइल और



बैंक अकाउंट जांचा नहीं गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल जांच की लापरवाही नहीं है, बल्कि मामले में और कारण भी हो सकते हैं। 2023 से जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और अपहृत का पता नहीं चला। अपहृत के भाई दीपक कयाल के वकील तरणज्योति तिवारी ने बताया कि परिवार को अपहृत की मानसिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, जबकि उसके बैंक अकाउंट की जानकारी मौजूद है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कुलतली थाने के इंसपेक्टर को सख्त चेतावनी दी और जांच में अगले कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की गई है।

बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार और हिंसा ‘कैंसर’ की तरह फैल रहे : राज्यपाल

कोलकाता, समाज्ञा : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और हिंसा यहां की राजनीति में कैंसर की तरह फैल रहे हैं। बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में दो गंभीर समस्याएं अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हैं - पहली हिंसा और दूसरी बेलगाम भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार द्वारा 'वंदे मातर' के आधिकारिक प्रस्तुतीकरण को लेकर जारी नए दिशा-निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि यह केवल राष्ट्रीय गीत ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का प्रतीक है। उनके अनुसार, यह गीत देश के लोगों को बिना भय अपनी बात रखने की आजादी का संदेश देता



है। हालांकि, उन्होंने बेलडांगा हिंसा मामले में एनआईए जांच को लेकर बंगाल सरकार की याचिका खारिज किए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः न्यायिक विषय है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना

चाहेंगे। साथ ही, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक कदम बताते हुए चुनाव आयोग की पहल का समर्थन किया।

हाई कोर्ट ने राज्य से जेलों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कैदियों की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य से जेलों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवांशु बसक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बाक रशीद की डिवीजन बेंच ने राज्य को यह रिपोर्ट 9 मार्च 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में जेलों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है या नहीं, खाली पदों पर नियुक्ति हुई है या नहीं, 1 जनवरी 2022 से जनवरी 2026 तक कितने कैदियों की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने पर उन्हें या उनके परिवार को मुआवजा दिया गया या नहीं, जैसी जानकारी शामिल हों। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताना आवश्यक है कि जेलों की क्षमता के मुकाबले कितने कैदी अधिक हैं, राज्य में कुल कितने जेल हैं, नए जेल बनाने पर अनुमानित खर्च और उसमें कितने कैदी रखे जा सकते हैं। रिपोर्ट में कैदियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी इंतजामों का विवरण भी शामिल होना चाहिए, जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा, और यदि कोई बच्चा माता-पिता के साथ जेल में है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था।

पूर्व रेलवे

निविदा का निस्तीकरण

ई-निविदा संख्या 262_2025-26, अनुमानित मूल्य: ₹.32,40,18,905.10, बयाना राशि: ₹. 17,70,100/-, निवृत्त तिथि/समय: दिनांक 23.02.2026 को 14.00 बजे, जो पूर्व में मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा द्वारा प्रकाशित की गई थी, को एल्ट्राट्रान्स तकनीकी कारण से 'निवृत्त' किया जाता है। HW-6/10/2025-26 निवृत्त सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: [@EasternRailway](https://www.instagram.com/EasternRailway) [@easternrailwayheadquarter](https://www.facebook.com/easternrailwayheadquarter)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र.: सीनियर डी.ई.ई.ई. (आर.एस. & जी.) बी.एस.पी./ओ.टी.बी./25-26-41, दिनांक 05.02.2026 कार्य का नाम:- 1. कार्य का विस्तृत भाग 'रनिम' रूप का 5 डबल डेड वागे कमरों के विस्तार और मौजूदा रसीदों और इंडकम का उन्मूलन। 2. विलासपुर डिवीजन: ADEN/SDL के क्षेत्रधिकार में अनुपपुर (APR) पर बंलिग्रस्त स्टॉल ओवरहेड टैंक के स्थान पर 2.25 लाख लीटर क्षमता वाला RCC ओवरहेड टैंक स्थापित करने की व्यवस्था। निविदा मूल्य- ₹. 46,04,653/-, अमानत राशि- ₹. 92,100/-, निविदा भेजने की तिथि व समय- दिनांक 06/03/2026, 15:00 Hrs. बजे।

विस्तृत जानकारी/निविदा दस्तावेज का विक्रय, पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण निविदा दस्तावेज जो हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है उससे डाउनलोड कर/देख सकते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी और से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता(जी)/खंडगुरु-721301, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए मांग के समक्ष उल्लेखित तारीख को दोपहर 12.00 बजे से पहले ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। क्रमांक एवं निविदा सूचना सं., कार्य का विवरण, निविदा मूल्य, बोली सुरक्षा/ई.एम.डी.: (1) 114-ईलसली-जी-केजीपी-25-26-41, दिनांक 09.02.2026, साऊथ सेक्टरमें खंडगुरु के अंजीन एक्सप्रेस/एसी/खंडगुरु के अंतर्गत बड़ी हुई लोड मांग का सामना करने के लिए एलटी एल्टीयु आरपी प्रणाली के स्वयं एवं एचटी एलटी एलटीयु के लिए पेश करने के लिए विद्युतीय कार्य, ₹. 3,75,17,484.55/- ₹. 3,37,600। (2) 114-एलसली-जी-केजीपी-25-26-55, दिनांक 09.02.2026: (i) पाश्चात्य में एलएलटी/एलपी/कांस्टाबल कार्यालय के निर्माण तथा (ii) पाश्चात्य में एलपी/एलटी/पाश्चात्य के नए टाइप-IV क्वार्टर के निर्माण के लिए विद्युतीय कार्य, ₹. 29,28,983.50/- ₹. 58,600। निविदा दस्तावेज की कीमत: दोनों के लिए शून्य। कार्य पूरा करने की अवधि: स्वीडिटी पत्र के जारी किए जाने की तारीख से क्रमांक 1 के लिए 12 महीने तथा क्रमांक 2 के लिए 6 महीने। जमा की तारीख: दोनों के लिए 04.03.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक। निविदा खुलने की तारीख: दोनों के लिए 04.03.2026। निविदा के परिपूर्ण विवरण, ब्यौरा, विनिर्देश हेतु इच्छुक निविदादातागण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देख सकते हैं तथा अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करें। किसी भी स्थिति में इस कार्य के लिए मैनुअल निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। टिप्पणी: प्रकाशित बोलीदातागण सभी निविदाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित रूप से www.ireps.gov.in देख सकते हैं। (PR-117)

पूर्व रेलवे

संक्षिप्त ई-निविदा सं. 02-डीसीटी-सीओएन-आरओबी-एसडीएच-25-26, दिनांक: 09.02.2026, उप मुख्य अभियंता/निर्माण/आरओबी/पूर्व रेलवे/सियालदह, आर.एम.एस. बिल्डिंग (दूसरी मंजिल), सियालदह, कोलकाता-700014 के द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा प्रणाली के तहत निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है: कार्य का नाम:- कार्य/डी/निर्माण/आरओबी/पूर्व रेलवे/सियालदह के कार्यक्षेत्र में सियालदह मंडल की बालीगंज जंक्शन-बजबज शाखा में किमी. 21/24-26 और किमी. 21/23-25 पर आकड़ा-नंगी स्टेशनों के बीच 1X43 मीटर (स्टील कम्पोजिट गार्ड) के साथ 02 (दो) लेन रोड ओवरब्रिज नं. बी-29ए (बीएटीए रोड ओवरब्रिज) का पुनर्निर्माण अनुमानित मूल्य: ₹.17.93 करोड़ (सामान), बयाना राशि: ₹. 10,45,500/-, निविदा कागजात का मूल्य: शून्य। समापन अवधि: 18 (अठारह) घंटा। खुलने की तिथि: दिनांक 05.03.2026 को 15.00 बजे। निविदा कागजात एवं अन्य विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा के लिए बोली उर्वरक वेबसाइट पर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा एवं तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। CON-67/2025-26 निवृत्त सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: [@EasternRailway](https://www.instagram.com/EasternRailway) [@easternrailwayheadquarter](https://www.facebook.com/easternrailwayheadquarter)

कुछ ट्रेनों का

परीक्षण के तौर पर ठहराव

नीचे उल्लेखित ट्रेनें उसके समक्ष उल्लेखित स्टेशनों में परीक्षण के तौर पर निम्नानुसार ठहरेंगी:-

ट्रेन सं. एवं नाम	स्टेशन	समय-सूची		ट्रवरा प्रभावी होने की तिथि
		आगमन	प्रस्थान	
13417 दीघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस	गान्धेखर	09.36	09.38	13.02.2026
वि. 12.02.2026 (जेसीओ) से प्रभावी	उरख	09.26	09.28	
13418 मालदा टाउन-दीघा एक्सप्रेस	गान्धेखर	11.33	11.35	12.02.2026
वि. 12.02.2026 (जेसीओ) से प्रभावी	उरख	11.46	11.48	
63510 साझा-बर्दमान एमईएमयू पैसेंजर	ईशानवडी	18.22	18.23	12.02.2026
वि. 12.02.2026 (जेसीओ) से प्रभावी	हॉल्ट			
63550 अंबाला-बर्दमान एमईएमयू पैसेंजर	ईशानवडी	19.22	19.23	12.02.2026
वि. 12.02.2026 (जेसीओ) से प्रभावी	हॉल्ट			
63549 बर्दमान-आसनसोल एमईएमयू पैसेंजर	ईशानवडी	12.58	12.59	12.02.2026
वि. 12.02.2026 (जेसीओ) से प्रभावी	हॉल्ट			

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

सियालदह मंडल के तहत स्टेशनों पर स्टॉल/आउटलेट

एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना के अधीन

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, सियालदह के द्वारा सियालदह मंडल के तहत 113 स्टेशनों पर 'एक स्टेशन एक प्रोडक्ट' योजना में भागीदारी के लिए देशी उत्पादों से जुड़े व्यक्तियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी), हाशिए पर रहने वाले या समाज के कमजोर वर्गों आदि से मुहबबंद पेट (एकल) में और निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएँ:- (1) परियोजना की अवधि: ● संतोषपुर, आकड़ा, कामागाटा मारु बजबज, अगरपाड़ा, दक्षिण दुर्गापुर -30 दिन दिनांक 02.03.2026 से शुरू। ● सुभाषग्राम-30 दिन दिनांक 04.03.2026 से शुरू। ● शासन रोड -30 दिन दिनांक 05.03.2026 से शुरू। ● नेतड़ा, चाम्पाहाटी, घुटियारी शरीफ, मगराहाट, सोण्डालिया, मथुरापुर रोड, हासनाबाद-30 दिन दिनांक 06.03.2026 से शुरू। ● दत्तपुर, दक्षिणेश्वर-30 दिन दिनांक 07.03.2026 से शुरू। ● मालतीपुर, भासिला, बमगांव जंक्शन, हदवपुर -30 दिन दिनांक 08.03.2026 से शुरू। ● बहार, बशीरहाट, कल्याणी शिल्पांचल, मदनपुर, काकदीप, पलता, दक्षिण बारासात-30 दिन दिनांक 09.03.2026 से शुरू। ● कल्याणपुर, होटोर-30 दिन दिनांक 10.03.2026 से शुरू। ● चंपापुर, कल्याणी सीमांत -30 दिन दिनांक 11.03.2026 से शुरू। ● भागवानगोला, बल्ला घाट, कासिमबाजार, लालगोला-30 दिन दिनांक 13.03.2026 से शुरू। ● इंडेन गाँव, गंगानगर, बागानगर, पालाचंडी, गेदे, कालीनारायणपुर जंक्शन, हबीबपुर -30 दिन दिनांक 14.03.2026 से शुरू। ● प्रिंसेपघाट, बिद्याधरपुर, पियाली-30 दिन दिनांक 15.03.2026 से शुरू। ● भागवानगोला, मुड़गाछा, बेलडांगा, बंधुयाडहरी, देबग्राम, रेजिनगर, पलासी, माझदिया, बगुला, कांकिनाड़ा, पायराडांगा, मुगी-30 दिन दिनांक 16.03.2026 से शुरू। ● बड़ा बाजार, पानिपुकर, बसुलडांगा, धपघरी, पालपाड़ा, सूर्यपुर, चाँदपाड़ा -30 दिन दिनांक 17.03.2026 से शुरू। ● शांतिपुर, गुमा, बामनागाछा, बल्ला घाट, कासिमबाजार, लालगोला-30 दिन दिनांक 18.03.2026 से शुरू। ● बादकुल्ला, कालिकापुर-30 दिन दिनांक 19.03.2026 से शुरू। ● गोबरडांगा, ठाकुरनगर, अशोकनगर रोड, न्यू बैरकपुर, दुर्गानगर, बिशरपाड़ा कोदालिया, बीरा, हाबरा, हालिशहर-30 दिन दिनांक 21.03.2026 से शुरू। ● जियागंज, आंडघाटा-30 दिन दिनांक 23.03.2026 से शुरू। कृष्णपुर, मुर्शिदाबाद, बहमपुर कोर्ट, फुलिया, कल्याणी घोषपाड़ा, देउला, धामुया, डायमंड हाबर, संग्रामपुर, कैनिंग, हाड़ोया रोड, चकदह, मध्यग्राम, नामखाना, बैरकपुर -30 दिन दिनांक 24.03.2026 से शुरू। ● गोपालनगर, बिनय बादल दिशरा बाग, टाकि रोड, तालदी-30 दिन दिनांक 27.03.2026 से शुरू। ● टाला, बड़ानगर रोड, बीरनगर, जयनगर मजिलपुर-30 दिन दिनांक 28.03.2026 से शुरू। ● ताहरपुर, सियालदह, बालीगंज जंक्शन-30 दिन दिनांक 29.03.2026 से शुरू। ● धुबुलिया, बानपुर, गोचरण, जगहल, टीटागढ़, काशीनगर हाल्ट, इच्छापुर-30 दिन दिनांक 31.03.2026 से शुरू। (2) टोकन पंजीकरण शुल्क: प्रत्येक स्टॉल हेतु 30 दिनों की अवधि के लिए प्रति एक स्टेशन एक प्रोडक्ट आउटलेट (3) आधारभूत संरचना: (i) स्टॉल/आउटलेट रेलवे द्वारा प्रदान किए जाएंगे। (ii) 15 दिनों के एक चरण के लिए प्रति एक स्टेशन एक प्रोडक्ट आउटलेट हेतु अधिकतम 20 यूनिट बिजली की स्वीकृति पंजीकरण शुल्क में नियमों के अंतर्गत शामिल बुनियादी सुविधा के रूप में दी जाएगी। 20 यूनिट की सीमा से अधिक के बिजली खर्च पर, अतिरिक्त यूनिटों के लिए, वास्तविक आधार पर प्रयोज्य शुल्क लागू रहेगा। (4) आवेदन जमा किया जाना: दिनांक 28.02.2026 को 15.00 बजे के अंदर। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, सियालदह, कक्ष सं. 44, डीआरएम कार्यालय, काइजर स्ट्रीट, कोलकाता-700014 को संबोधित करते हुए कागजात की प्रतिलिपि (जैसा कि ऊपर पात्रता मानदंड में उल्लिखित है) के साथ संगठन के लेटरहेड/सादे सफेद कागज की शीट में आवेदन संबंधित स्टेशनों के स्टेशन मास्टर/स्टेशन प्रबंधक/बुकिंग सुपरवाइजर के कार्यालय में निर्धारित स्थान पर मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में: दिनांक 28.02.2026 को 16.00 बजे ऊपर उल्लिखित स्थान पर खुली लाईटी/सार्वजनिक ड्रा निकाला जाएगा। चिह्नित उत्पादों सहित स्टेशनों के नाम, भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड, समर्थित कागजात और ईओआई कागजातों के साथ विस्तृत नियम और शर्तों को आधिकारिक वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in से देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है और इन्हें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, सियालदह के कार्यालय में सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, सियालदह

पूर्व रेलवे

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

MATRIMONIAL

EDUCATION

OBITUARY

PROPERTY

NAME CHANGE

REMEMBRANCE

RECRUITMENT

PUBLIC NOTICE

DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadv@gmail.com | www.samagya.in

81, Chintamani Dey Road, Howrah 711 101, Mobile: 70444 44522

किसानों को 15 फरवरी तक कृषकबंधु का पैसा मिलना चाहिए, बैठक में कृषि मंत्री ने दिया सख्त निर्देश

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले कृषकबंधु परियोजना के लिए आवर्दित पैसा किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। बुधवार को यह संदेश कृषि मंत्री शोभनदेव चटर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग के अलग-अलग परियोजनओं के शेष काम जल्दी पूरे किए जाएं। मंत्री ने निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर देखें कि कृषकबंधु परियोजना, फसल बीमा और खेती की मशीनरी जैसे

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से भारत के भविष्य के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को मिल रही मजबूत नींव

मुंबई/कोलकाता : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से प्राप्त अनुभव को भारत के भविष्य के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विकास की मजबूत नींव माना जा रहा है। 508 किलोमीटर लंबी यह हाई स्पीड रेल परियोजना जापान की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निर्माणाधीन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से ट्रेक, सिग्नलिंग, रो-लिंग स्टॉक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में देश की तकनीकी क्षमता सुदृढ़ हो रही है। परियोजना के तहत स्वदेशीकरण और नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। भारी निर्माण मशीनरी, स्लैब ट्रेक सामग्री

आसनसोल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव घोषित
कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर प्रायोगिक आधार पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 12 फरवरी यानी आज से लागू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 13417 दीधा-मालदह टाउन एक्सप्रेस तथा 13418 मालदह टाउन-दीधा एक्सप्रेस को दो स्टेशनों पर नया ठहराव दिया गया है। ये ट्रेनें पॉन्डवेयर स्टेशन पर सुबह 09:36 बजे और 11:33 बजे पहुंचेंगी तथा दोनों का ठहराव समय 2 मिनट होगा। इसी प्रकार, यही दोनों ट्रेनें उखरा स्टेशन पर 09:26 बजे और 11:46 बजे पहुंचेंगी, जहां भी 2 मिनट का ठहराव निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कुछ मेमू पैसेंजर ट्रेनों को ईशानचंडी हॉल्ट पर ठहराव दिया गया है। ट्रेन संख्या 63510 झाझा-वर्दवान मेमू पैसेंजर शाम 18:22 बजे पहुंचेगी और 18:23 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 63550 अंडाल-वर्दवान मेमू पैसेंजर 19:22 बजे पहुंचेगी और 19:23 बजे रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 63549 वर्दवान-आसनसोल मेमू पैसेंजर 12:58 बजे और पहुंचेगी और 12:59 बजे प्रस्थान करेगी।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव
कोलकाता, समाज्ञा : पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत कई प्रमुख ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 15709/15710 मालदह टाउन-न्यू जलपाईगुड़ी-मालदह टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस को 14 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए श्रीपुर और मलाहार स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा। इसी प्रकार, 14 फरवरी 2026 से 13175 सियालदह-सिलचर कंचनजंघा एक्सप्रेस तथा 13 फरवरी से 13176 सिलचर-सियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस को हरिश्चंद्रपुर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया गया है। 13 फरवरी से 13159 कोलकाता-जोगबनी एक्सप्रेस और 14 फरवरी से 13160 जोगबनी-कोलकाता एक्सप्रेस अब भालुका रोड स्टेशन पर भी रुकेगी। इसके अलावा, 11 फरवरी से 12552 कामाख्या-एसएमवीटी बेंगलुर एसी एक्सप्रेस तथा 14 फरवरी से 12551 एसएमवीटी बेंगलुर-कामाख्या एसी एक्सप्रेस को फालकाटा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।



मंत्री ने खरीफ सीजन में किसानों को कृषकबंधु परियोजना के लिए आवर्दित पैसा देने के लिए 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी है। अगर किसी वजह से किसानों को

पूर्व बर्दवान में माध्यमिक परीक्षा केंद्र पर हड़कंप, परीक्षार्थी के बैग से मिला ‘बंदूक’ जैसा सामान

पूर्व बर्दवान, समाज्ञा : माध्यमिक के जीवन विज्ञान की परीक्षा के दौरान बुधवार को पूर्व बर्दवान जिले में एक परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी कथित तौर पर बंदूक लेकर पहुंच गया, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, बाद में, जांच में पता चला कि वह असली बंदूक नहीं, बल्कि बंदूक के आकार का एक गैस लाइटर था। जानकारी के अनुसार, बर्दवान उदयपल्ली शिक्षा निकेतन में रामकृष्ण स्कूल का सीट पड़ा है। रामकृष्ण स्कूल का यह छात्र अन्य दिनों की तरह ही परीक्षा देने केन्द्र पर पहुंचा था। निर्धारित समय पर जब परीक्षार्थियों के बैग की जांच की जा रही थी,

यह पैसा मिलने में कोई दिक्कत आती है, तो कृषि अधिकारी उनके घर जाकर उसे ठीक करेंगे। बता दें कि यह पैसा देने का काम 28 जनवरी से राज्य के हर जिले में शुरू हो गया है। बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से जानना चाहा कि किस जिले में काम कितना आगे बढ़ा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस बारे में मुख्यमंत्री के ग्रीवांस सेल में मिली सभी शिकायतों की जांच की जाए और शिकायत करने वाले किसानों के घर जाकर समस्या का जल्द समाधान किया जाए। अगर आधार, केवाईसी जैसी कोई दिक्कत

है, तो यह देखा जाए कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। खबर यह भी है कि बैठक में खेती-बाड़ी करने वाले मजदूरों को कृषकबंधु देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। शोभनदेव ने ज़िला कृषि अधिकारियों को खरीफ सीजन से पहले जमीन में ‘माइक्रोन्यूट्रिएंट्स’ में ज़िक की मात्रा बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि चावल की पैदावार बेहतर हो सके। मंत्री ने ज़िला अधिकारियों से इस बारे में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से सलाह लेने को भी कहा।

लाइटर को उंगलियों के बीच घुमाते हुए स्कूल आया था। इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि यह महज मजाक था या इसके पीछे कोई और कारण। इतनी बड़ी घटना के बावजूद छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई और अन्य सभी परीक्षार्थियों ने सुरक्षित रूप से परीक्षा दी। छात्र के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले को लेकर आवश्यक जांच कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कोलकाता, समाज्ञा : चिल्ड्रन्स मेटल हेल्थ वीक के अवसर पर एसपीके जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी ने अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन (ईसीए) के सहयोग से प्ले, अटेंचमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यालयी परिवेश में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया। सत्र के दौरान खेल-आधारित शिक्षा, सुरक्षित भावनात्मक जुड़ाव (सिंक्वोर अटेंचमेंट) और भावनात्मक विकास को बच्चों के समग्र कल्याण और शैक्षणिक उपलब्धियों से सीधे जुड़ा बताया गया। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि भावनात्मक

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का निर्माण शुरू विरोध कर रहे लोग पीछे हट जाएं, लोग अपना धर्म मानने के लिए आजाद : हुमायूं कबीर

➤ जेयूपी प्रमुख आज

पलाशी से बेलडांगा तक 22

किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा

मुर्शिदाबाद : तृणमूल कांग्रेस से निर्लंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बहुचर्चित मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया। बताया गया है कि बेलडांगा के रेजिनगर में इस मस्जिद का निर्माण दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा और इसकी लागत लगभग 50-55 करोड़ रुपये आयेगी। यह मस्जिद 11 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है और इसमें लगभग 12,000 लोगों के नमाज अदा करने की क्षमता होगी। इस दिन, धार्मिक नेताओं एवं सैकड़ों स्थानीय लोगों के उत्साह के बीच, निर्माण श्रमिकों ने रेत में इमारत के लिए ईंट रखने का समारोह शुरू किया। कबीर ने कहा कि कई पक्षों के विरोध के बावजूद मस्जिद का निर्माण कार्य निर्धारित



कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों से मैं कहना चाहंगा कि वे हट जाएं। लोगों को अपने-अपने धर्मों का पालन करने तथा मंदिर, गिर्जाघर या जो चाहें बनाने की पूरी आजादी है। मैं इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूंगा। मेरा प्रयास अल्लाह को प्रसन्न करना और अपनी धार्मिक आस्था को निभाना है, किसी पर कुछ थोपना नहीं। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण को रोकने वाली धरती पर कोई ताकत नहीं है। अल्लाह की कृपा से हम दो साल के भीतर इसका निर्माण पूरा कर लेंगे। इसे बनाने में 50-55

करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हालांकि, कबीर ने घोषणा की कि बोर्ड परीक्षाएं होने के चलते वह फिलहाल अपनी 'बाबरी यात्रा' - नदिया के पलाशी से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार तक 235 किलोमीटर की रैली - को स्थगित रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, वह आज पलाशी से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की, पदयात्रा करेंगे। कबीर ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य के 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से 135 पर प्रत्याशी खड़ा कर आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों को टक्कर देगी।

मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरुकता अभियान के लिए ‘पैडयुमन’ प्रीति मिंज सम्मानित

जलपाईगुड़ी : राज्य सरकार ने मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में एक दशक से अधिक के योगदान को मान्यता देते हुए ‘पैडयुमन’ के नाम से लोकप्रिय प्रीति मिंज को सम्मानित किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, प्रीति मिंज को यह सम्मान दुसर्पक्ष क्षेत्र के दुर्स्थ चाय बागान क्षेत्रों में किशोरियों और युवतियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार के मंत्री बुलू चिक बराइक ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले के ओडलाबारी स्थित मिंज के



आवास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से उन्हें एक प्रमाण पत्र सौंपा। बता दें कि पिछले 10 वर्षों से, मिंज चाय बागान क्षेत्रों में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं, अज्ञानता और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। वह घर-घर जाकर लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में परामर्श दे रही हैं, सुरक्षित प्रथाओं के महत्व पर जोर देने के अलावा सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। मिंज को इससे पहले भी कई स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

एसपीके जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी ने अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन के साथ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किया

कोलकाता, समाज्ञा : चिल्ड्रन्स मेटल हेल्थ वीक के अवसर पर एसपीके जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी ने अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन (ईसीए) के सहयोग से प्ले, अटेंचमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यालयी परिवेश में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया। सत्र के दौरान खेल-आधारित शिक्षा, सुरक्षित भावनात्मक जुड़ाव (सिंक्वोर अटेंचमेंट) और भावनात्मक विकास को बच्चों के समग्र कल्याण और शैक्षणिक उपलब्धियों से सीधे जुड़ा बताया गया। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि भावनात्मक



स्वास्थ्य को केवल परामर्श सत्रों तक सीमित न रखकर विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, कक्षा संवाद, शिक्षण पद्धतियों और पारिवारिक वातावरण में भी शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की भूमिका पर चर्चा करते हुए

अन्नन्ता, ने किया। उन्होंने भावनात्मक संकेतों की पहचान, विश्वास -आधारित संबंध निर्माण और अभिभावकों के साथ समन्वय जैसे व्यावहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में डॉ. सुमन सूद, डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल, बी.डी. मेमोरियल जूनियर; एडवाइजर, आई वी डब्ल्यू एस एवं बी.टी.एम.आई.; तथा नेशनल कोर कमिटी मेंबर, ईसीए, की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर एस-पीके जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी की प्रिंसिपल डॉ. जयिंता गांगुली ने कहा कि भावनात्मक कल्याण बच्चों के समग्र विकास का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे सत्र जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जुपिटर इंटरनेशनल ने तीसरी सोलर सेल मैनुफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर उत्पादन क्षमता दोगुनी की

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता स्थित जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के बड़ी में अपनी तीसरी सोलर सेल मैनुफैक्चरिंग यूनिट का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया है। इस विस्तार के साथ कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है, जो भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कंपनी ने अपने मौजूदा 959 मेगावाट उत्पादन आधार में 1 गीगावाट मोनो पीईआरसी सोलर सेल क्षमता जोड़ी है, जिससे कुल स्थापित क्षमता करीब 2 गीगावाट पहुंच गई है। नई यूनिट के उच्च दक्षता वाली मोनो पीईआरसी तकनीक पर केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाना है। इस विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और उन्नत सौर विनिर्माण में कुशल ग्रीन जॉब्स का सृजन होगा। कंपनी आगे 1.25 गीगावाट टॉपकॉन सोलर सेल लाइन स्थापित करने की दिशा में भी कार्यरत है। चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आलोक गरोडिया ने इसे कंपनी के विकास में अहम मील का पत्थर बताया।

जेनरेशन लार्ज की असली आवाज के साथ सीग्राम्स रॉयल स्टैंग बूमबॉक्स का भव्य कमबैक

कोलकाता, समाज्ञा : बॉलीवुड के सदाबहार गीतों और हिप-हॉप की ऊर्जावान धुनों का अनोखा संगम पेश करने वाला प्रतिष्ठित म्यूजिक फेस्टिवल सीग्राम्स रॉयल स्टैंग बूमबॉक्स अपने चौथे सीजन के साथ वापसी कर रहा है। पिछले सीजनों की सफलता के बाद इस बार आयोजन को और भव्य रूप दिया गया है। नया सीजन 21 फरवरी को कोलकाता से शुरू होगा, इसके बाद विशाखापत्तनम (7 मार्च), मुंबई (21 मार्च) और मोहाली (28 मार्च) में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल युवाओं की बदलती सांस्कृतिक रुचियों-संगीत, फैशन, फूड और गेमिंग-को एक मंच पर लाने के लिए जाना जाता है। इस वर्ष की प्रस्तुति में अंतरराष्ट्रीय कलाकार एलन वॉकर के साथ बादशाह, अरमान मलिक, डिवाइन, नीति मोहन, निकिता गांधी, रश्मीत कौर, श्रीराम चंद्र और बैंड फॉसिल्स शामिल होंगे। रक्तार, डिनो जेम्स और डीजे साहिल गुलाटी भी मंच संभालेंगे। गेमिंग प्रेमियों के लिए पायल थारो के साथ विशेष इंटेलिक्टिव सेगमेंट रखा गया है। यह फेस्टिवल लाइव म्यूजिक अनुभव को नई पहचान देने की दिशा में एक और कदम है। टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है।

अमेजन प्राइम ने 2025 में भारत में दी सबसे तेज़ डिलीवरी, ग्राहकों को कराई बड़ी बचत

कोलकाता, समाज्ञा : अमेजन ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 भारत में प्राइम सदस्यों के लिए अब तक का सबसे तेज डिलीवरी वाला साल रहा। कंपनी के अनुसार, 55 करोड़ से अधिक उत्पादों की डिलीवरी उसी दिन या अगले दिन की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। अमेजन ने बताया कि प्राइम सदस्यों ने औसतन अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क से दोगुने से अधिक की बचत की, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत सदस्यों ने अपनी फीस से आठ गुना तक की बचत हासिल की। कंपनी को 70 प्रतिशत से अधिक नए प्राइम सदस्य शी-मेट्रो शहरों से मिले, जो सेवा की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। प्राइम सदस्य मुफ्त और तेज डिलीवरी के अलावा हिप्पेस ऑफर, कैशबैक, प्राइम वीडियो, अमेजन म्यूजिक, प्राइम गेमिंग और प्राइम रीडिंग जैसे डिजिटल लाभ भी प्राप्त करते हैं। अमेजन इंडिया के प्राइम प्रमुख अभिनव अग्रवाल ने कहा कि कंपनी तेज, क्फियायती और सुविधाजनक सेवाएं देने के लिए लगातार निवेश कर रही है।

कम से कम 30 से 45 मिनट पैदल चलना। अगर एक बार में ज्यादा चलना संभव न हो तो कम से कम तेज चाल में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम टहल लें। सुबह जगने के बाद आप आधे घंटे टहल लें। हर दिन चलने से सेहत द्रुत रूखेगा और वजन भी कम होने

न्यूज़ इन ब्रीफ

भारत और थाईलैंड की वायुसेनाएं आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास कर रहीं

नयी दिल्ली: रॉयल थाई वायुसेना और भारतीय वायुसेना आपसी समन्वय और तालमेल को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं जिसमें भारत के लड़ाकू विमान एस्यू-30 एमकेआई के अलावा ईंधन भरने वाला विमान आईएल-78 और अन्य महत्वपूर्ण साजो-सामान को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभ्यास नौ फरवरी को शुरू हुआ जो 13 फरवरी तक जारी रहेगा। भारतीय वायु सेना ने बुधवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में हवाई अभ्यास के बारे में जानकारी साझा की। भारतीय वायु सेना ने पोस्ट किया, "भारतीय वायु सेना और रॉयल थाई वायुसेना एक संयुक्त हवाई अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी समन्वय और तालमेल को बढ़ाएगा।"

पंजाब: सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी को लेकर प्रदर्शन किया

चंडीगढ़: पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने एक संगीत निर्माता और दो अन्य लोगों पर विविध अनियमितताओं के आरोप वाली उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया। सिद्धू के माता-पिता की शिकायत उनके दिवांगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के लिए बकाया रॉयल्टी भुगतान से संबंधित वितीय विवाद से जुड़ी है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर बुधपदी सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 26 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। बलकौर सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर अपने छोटे बेटे के साथ मानसा में एसएसपी कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठे तथा उन्होंने संगीत निर्माता व दो अन्य लोगों के खिलाफ अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की।

केरल ने बुजुर्गों के कल्याण पर केंद्रित नयी नीति को मंजूरी दी

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने बुधवार को नयी बुद्धजन नीति को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि यह किसी भी राज्य द्वारा लाई गई पहली ऐसी नीति है, जो बुजुर्ग नागरिकों की गरिमा और कल्याण की सुरक्षा के लिए समावेशी और समानता पर आधारित ढांचा तय करती है। यह नीति इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि राज्य में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में यह कुल जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत है-जो देश में सबसे अधिक और सबसे तेजी से बढ़ने वाला अनुपात है। यह आंकड़ा 2036 तक बढ़कर कुल आबादी का 23 प्रतिशत होने की संभावना है। राज्य की सामाजिक कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा कि यह नीति सक्रिय और स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देगी और राज्य में बुजुर्गों के सामाजिक तथा मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करेगी।

रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी का मकसद मुंबई में दहशत फैलाना था: पुलिस

मुंबई: फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी में शामिल आरोपियों का मकसद शहर में दहशत फैलाना था। पुलिस ने अदालत को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कठोर कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। विशेष मकोका अदालत ने पांचों आरोपियों को 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, एक फरवरी की देर रात करीब 12.45 बजे जुहू स्थित शेट्टी के आवास की पहली मंजिल पर कम से कम पांच बार गोलियां चलाई गईं। एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर लगी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा का जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ इस मामले की जांच कर रहा है। अधिकारी ने कहा, कुछ आरोपी पहले से ही गंभीर अपराधों में शामिल हैं। अपराध शाखा ने मामले में मकोका की कड़ी धाराएं लगाई हैं।

वंदे भारत में एसी चेयर कार का किराया चीन, जापान और फ्रांस की तुलना में काफी कम : वैष्णव



नयी दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि वंदे भारत एसी चेयर कार का 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा का किराया लगभग 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर है, जो चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों से काफी कम है। वैष्णव के अनुसार, इन देशों में किराया 7 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर तक होता है। वंदे भारत ट्रेनों के किराये के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा, 'रेल मंत्रालय विभिन्न प्रकार की यात्री सेवाओं के किराये

का निर्धारण करते समय सेवा की लागत, सेवा का स्तर, दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के प्रकार, वहनीयता, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर गौर करता है।' उन्होंने बताया कि वंदे भारत सेवाएं फरवरी 2019 में शुरू की गई थीं और वर्तमान में 82 मार्गों पर 164 ट्रेनें चल रही हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि वंदे भारत ट्रेनें एक विशिष्ट किराया संरचना और बेहतर 'सस्पेंशन' सिस्टम, सेमी-हाई-स्पीड संचालन के साथ तेज गति, स्वचालित द्वार, आरामदेह सीटें,

फिल्म जगत ने हमारा साथ दिया है, हम आभारी हैं: राजपाल यादव की पत्नी राधा ने कहा



मुंबई: अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने बुधवार को कहा कि 'चेक बाउंस' मामलों में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के बाद फिल्म उद्योग के कई लोग हास्य कलाकार के समर्थन में आगे आए हैं। 'बकाया राशि चुकाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा और समय देने की याचिका खारिज किए जाने

के बाद राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अभिनेता को करीब नौ करोड़ रुपये का भुगतान करना है। यादव को 'मुझसे शादी करोगी', 'वक्त', 'फिर हेरा फेरी', 'पाटनर', 'भूल भुलैया', 'हंगामा' और 'चुप चुप के' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाता है। फिल्म उद्योग से अभिनेता सौर सूट, गुमीत चौधरी और संगीतकार राव इंदुजीत यादव सहित कई लोगों ने परिवार को आर्थिक सहायता की पेशकश की तथा अन्य लोगों से भी आगे आने की अपील की। राधा यादव ने पीटीआई-भाषा से कहा, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। फिल्म उद्योग ने बहुत सहयोग किया है। जो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हम सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। राजपाल यादव के 25 वर्षों से

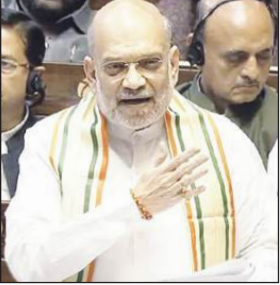
वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य, स्वास्थ्य कारणों से रिहा नहीं किया जा सकता: केंद्र

नयी दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि हिरासत में लिये जाने के बाद से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 24 बार चिकित्सकीय जांच की जा चुकी है और वह 'पूरी तरह स्वस्थ' है तथा चिंता की कोई बात नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ को बताया कि जिन स्थितियों



में वांगचुक को हिरासत में लिया था उम्में कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा करना संभव नहीं है।

अब तक 8,710 कृषि सहकारी समितियां स्थापित हुईं, 27 प्रतिशत लक्ष्य हासिल : अमित शाह



नयी दिल्ली: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 2024-25 और 2025-26 के दौरान 32,752 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) गठित करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 8,710 पैक्स स्थापित की गई हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 27 प्रतिशत है। शाह ने एक सवाल के लिखित जवाब में

उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 32,752 पैक्स गठित करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 8,710 पैक्स गठित की गई हैं, जो उद्योग दो साल की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 27 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक पैक्स ओडिशा में (1,543) स्थापित किए गए। उसके बाद राजस्थान (1,387), उत्तर प्रदेश (1,099), मध्यप्रदेश (621) और उत्तराखंड (621) का स्थान रहा। गुजरात में 525 पैक्स, असम और छत्तीसगढ़ में 469-469, महाराष्ट्र में 149 और हिमाचल प्रदेश में 116 पैक्स स्थापित किए गए।

भारतीय वायु सेना नई पीढ़ी के और अधिक विमान शामिल करने की इच्छुक: उपप्रमुख

नयी दिल्ली: वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायु सेना अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और भी अधिक विमानों को शामिल करने की इच्छुक है। कपूर वायु शक्ति अभ्यास से पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। राफेल के बारे में उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल निश्चित रूप से अन्य नायकों के साथ-साथ एक नायक था। जी हां, राफेल इन दिनों एक चर्चित शब्द से चर्चा के केंद्र में है। वायुसेना के उपप्रमुख ने कहा,



वायुसेना और भी कई एसआरएएफ (बहु-भूमिका लड़ाकू विमान) को

चारधाम तक रेल संपर्क के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है : रेल मंत्री वैष्णव

सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि चारधाम तक रेल संपर्क के लिए ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नामक एक नयी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है तथा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रेल संपर्क के विस्तार के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा सांसद अनिल बलूनी और अजय भट्ट के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में 40,384 करोड़ रुपये की लागत वाली 216 किलोमीटर की कुल लंबाई की तीन नयी लाइन को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 16 किलोमीटर हिस्सा चालु हो गया है और मार्च 2025 तक 19,898 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

मिनी पैंटी, सीसीटीवी और कवच जैसी सुविधाओं के साथ एक अलग यात्री सेवा खंड के रूप में संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि वहनीयता को ध्यान में रखते हुए, इन ट्रेनों का किराया सेवा लागत से कम रखा गया है। वैष्णव ने कहा, 'वंदे भारत एसी चेयर कार का 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा का किराया लगभग 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर है, जो चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों में इसी तरह की सेवाओं के किराये से काफी कम है, जहां यह 7 रुपये से 20 रुपये प्रति किलोमीटर

तक है।' वहीं, ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल नहीं करने से संबंधित कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को औसतन 45 प्रतिशत की रियायत मिलती है। वैष्णव ने कहा, 'भारतीय रेलवे ने 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। इसका मतलब है कि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 45 प्रतिशत की रियायत मिलती है।'

स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाने के लिए मिजोरम ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी की

आइजोल: मिजोरम युवा आयोग (एमवाईसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों में राज्य के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यहां एआरओ मुख्यालय में 'यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) के अध्यक्ष मालसामजुआला राल्ते और एआरओ निदेशक कर्नल प्रकाश कुमार सिंह के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस सहयोग को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि वार्षिक भर्ती रैलियों को स्थानीय उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हुए दोनों पक्षों ने स्थानीय उपाध्यक्षों की सफलता दर बढ़ाने के वास्ते एक व्यापक सहयोग तंत्र पर सहमति जताई है।

असम-अरुणाचल सीमा विवाद: पक्के केसांग-विश्वनाथ जिले में सीमा पर पिलर लगाने का काम शुरू



और स्थिरता आने के साथ-साथ पड़ोसी क्षेत्रों के बीच शांति, सद्भाव और सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। पक्के केसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बियुराम वाहगे ने इसे 'ऐतिहासिक' करार दिया। वाहगे ने कहा, "यह लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के

भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा, 2030 तक 5जी उपभोक्ता 100 करोड़ होने का अनुमान: सरकार

नयी दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कहा कि वाई-फाई कनेक्टिविटी की 4जी तकनीक में भारत विश्व के पीछे था, 5जी में विश्व के साथ चला है और 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह भी कहा

कि अभी देश में 5जी कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ है और 2030 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की मिताली बाग के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, 'वाई-फाई कनेक्टिविटी की 4जी तकनीक में भारत विश्व के पीछे था, 5जी में विश्व के साथ चला है

जन प्रतिनिधि काम न करे तो मतदाताओं के पास उसे वापस बुलाने का अधिकार हो : राघव चड्ढा

नयी दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को शुन्यकाल के दौरान सदस्यों ने काम नहीं करने की स्थिति में जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने, प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए बड़े हादसों और अभिभावकों की वृद्धावस्था में देखभाल न किए जाने जैसे मुद्दे उठाए तथा सरकार से अपेक्षित कदम उठाने का अनुरोध किया। शुन्यकाल में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को मतदान का अधिकार है उसी तरह, काम नहीं करने की स्थिति में 'राइट टू रिकॉल' (जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) भी मतदाताओं के पास होना चाहिए। चड्ढा ने कहा "अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को चुन सकता है तो उसे उन्हें काम न करने पर हटाने का हक भी होना



चाहिए। 'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था मतदाताओं को अधिकार संपन्न बनाएगी ताकि अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो उसे हटाया जा सके।' उन्होंने कहा कि सांसद या विधायक चुने जाने के बाद अगर जन प्रतिनिधि काम न करे तो जनता के पास पांच साल तक बर्दाश्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। "गलत नेता को चुनने के एक लालत फैसले से पूरा क्षेत्र, पूरा समय बर्बाद होता है और लाखों मतदाता इसका खामियाजा भुगतते हैं," चड्ढा ने स्पष्ट

किया कि 'राइट टू रिकॉल' नेताओं के खिलाफ हथियार नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि 'राइट टू रिकॉल' के तहत मतदाता एक निर्धारित और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। चड्ढा ने कहा कि भारत में पहले ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की व्यवस्था है और सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, स्विटजरलैंड और कनाडा सहित दुनिया के 20 से अधिक लोकतांत्रिक देशों में 'राइट टू रिकॉल' की व्यवस्था है। हमारे देश में कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था है।'

पंजाब: आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; आईईडी बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिमोट कंट्रोल से संचालित एक आईईडी की बरामदगी के साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) ने खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि एक विदेशी पिस्तौल और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। यादव ने 'एक्स' पर कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी

गौरव गोगोई के 'पाकिस्तान से संबंधों' पर एसआईटी की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी : हिमंत विश्व शर्मा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई के कथित 'पाकिस्तान संबंधों' पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट को आगे की विस्तृत जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शर्मा ने कहा कि इससे पहले सांसद द्वारा हाल ही में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में



पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति के संपर्क में था। उन्होंने कहा, 'आतंकी सामग्री की खेप सीमा पर भेजी गई थी और शहर के बाहरी इलाके में एक निर्धारित स्थान से बरामद की गई।' उन्होंने कहा, 'इस परिष्कृत विस्फोटक

उपकरण (आईईडी) का इस्तेमाल पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में लक्षित हमलों के लिए किया जाना था।' यादव ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच जारी है।



किए गए 'खुलासों' को शामिल करने के लिए रिपोर्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसमें रावलपिंडी जिले की

प्रधानमंत्री 14 फरवरी को भारतीय वायुसेना के एयर शो से पहले असम के राजमार्ग पर उतरेंगे

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले में हाइवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) पर उतरेंगे। इस सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा एक भव्य हवाई प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री शनिवार सुबह नयी दिल्ली से चाबुआ वायुसेना अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे। वहां से वे उड़ान भरकर जिले के मोरान स्थित ईएलएफ पर उतरेंगे।' इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के लगभग 16 विमानों के हवाई प्रदर्शन का गवाह बनेंगे जो 30 मिनट तक या तो यहां उतरेंगे या इसके ऊपर से उड़ान भरेंगे। शर्मा ने कहा, 'इस हवाई प्रदर्शन में राफेल, सुखोई और भारतीय वायुसेना के अन्य विमान भाग लेंगे, और कई लड़ाकू विमान भी इस पट्टी पर उतरेंगे। ईएलएफ पर यह पहला ऐसा विस्तृत अभ्यास होगा।'



मुख्यमंत्री ने बताया कि मोदी ईएलएफ से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां से वे चुनाबी राज्य की अपनी एक दिवसीय यात्रा के अगले चरण पर पहुंचेंगे। इससे पहले शर्मा ने कहा था कि ईएलएफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा तैयारियों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायु सेना के समन्वय से डिब्रूगढ़-मोरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत निर्मित मोरान ईएलएफ को मोरान और डेमो के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 4.2 किलोमीटर के हिस्से में विकसित किया गया है।



और 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र का विकास : चौहान

अगरतला: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। चौहान ने विपक्षी कांग्रेस और माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर वीबी-जी राम जी योजना के खिलाफ 'नकारात्मक अभियान' चलाने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामिण) योजना भारत को एक विकसित देश बनाने की रूपरेखा है। उन्होंने कहा, 'वीबी-जी राम जी का



उद्देश्य रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन विपक्षी दलों कांग्रेस और माकपा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए इसके खिलाफ नकारात्मक अभियान चला रहे हैं।" चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने हाल में लोकसभा में पेश किए गए बजट में वीबी-जी राम जी के लिए

रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की है। उन्होंने कहा, 'केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने ग्राम पंचायत योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। राज्यों के योगदान की जीएड टो कुल व्यय 1,51,282 करोड़ रुपये होगा और वित्त आयोग ग्राम पंचायतों को सीधे 55,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगा।'

